तिब्बत देश

नेपाल बना चीन का नया उपग्रह

देशों के इतिहास के बारे में एक मशहूर शेर का हिस्सा है : 'लम्हों ने ख़ता की थी, उम्रों ने सज़ा पायी''। पिछले लगभग साठ साल के दौरान आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जब ऐसा लगता है मानो शायर ने तिब्बत के संदर्भ में इस शेर को भारत के लिए ही लिखा था।

1949 में जिस समय चीन ने तिब्बत के पूर्वी प्रांतों पर सैनिक कब्जा जमाया और बाकी बचे हुए तिब्बत के लिए तिब्बत सरकार को धमकाना शुरू किया उस समय सदियों की गुलामी से बाहर निकला भारत अपना नया राजनीतिक नक्शा बनाने में व्यस्त था। राजसी रियासतों के भारत में शामिल होने के इस सिलसिले को देखते हुए चीन की इस हरकत ने नेपाल के राजा को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि नेपाल की सुरक्षा के लिए उसे भी भारत में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा भी। लेकिन नए बने कम्युनिस्ट चीन की ताकत से अभिभूत और उसके साथ भाईचारे वाले संबंधों के सपनों में हिलोरें लेती भारत सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

उसके बाद तिब्बत पर चीन का पूरा कब्जा हो जाने पर भी भारतीय शासक अपने बुने हुए सतरंगी इंद्रधनुष की पींग पर झूलते जमीन की असलियत से कोसों दूर सपनों की दुनिया में खोए रहे। और जब चीनी हुक्मरानों ने तिब्बत की जमीन को छावनी की तरह इस्तेमाल करके 1962 में भारत पर हमला किया और उसे हार की धूल चटाई तब तक बात हाथ से बुरी तरह निकल चुकी थी। खयाली इंद्रधनुष की ऊंचाई से धड़ाम गिरे अपमानित भारत के मन में चीन के प्रति जिस दहशत ने घर जमाया वह आज भी चीन के बारे में उसकी हर नीति में से बुरी तरह झलकती है। ऐसे में यह देखकर हैरानी नहीं होती कि चीन से पिटे लाचार भारत के प्रति उसके किसी पड़ोसी देश ने कभी प्यार, इज्जत या विश्वास की नजर से देखने की बात नहीं सोची। अगर बाद वाले बरसों में नेपाल के शासकों ने चीन को नाराज न करने की नीति अपनायी और इस कारण भारत से वाजिब दूरी बनाए रखी तो यह सब स्वभाविक ही था।

बाद वाले बरसों में भारत में यह देखकर तसल्ली महसूस की जाती रही कि अगर नेपाल की सरकार भारत के साथ बहुत गहरा रिश्ता नहीं रख रही तो वह चीन के साथ भी सुरक्षित दूरी बनाए हुए है। भारतीय नीति निर्धारक इसे नेपाल की इस नीति को चीन और भारत के साथ 'ईक्वी डिस्टेंस पालिसी' कहकर खुद को सांत्वना देते आए हैं। लेकिन पिछले आठ–दस साल से नेपाल के मोर्चे पर होने वाले बदलाव ने अब भारतीय नीति निर्धारकों की नींद उड़ानी शुरू कर दी है। वे यह देखकर बुरी तरह परेशान हैं कि नेपाल सरकार की पहली वरीयता चीन को खुश करना है और भारत से हर तरह की मदद डकारने के बाद भी वह बात–बात पर उसे घुड़कियां देने लगी है। वे इस बात से भी सकते में हैं कि जहां एक ओर भारत को तोड़ने में लगे अलगाववादी भारतीय संगठनों को नेपाल में काम करने के लिए पूरी जमीन मिली हुई है वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की शह पर काम करने भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों के लिए खुले बार्डर वाला नेपाल एक स्वर्ग बन चुका है। मौका आने पर अगर इन सब ताकतों के तालमेल में चीन सरकार का हाथ सिद्ध होता है तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए।

भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में नेपाल का झुकाव खुद स्वर्गीय महाराजा वीरेंद्र के जमाने में ही दिखाई देने लगा था। बाद में उनकी हत्या के बाद गद्दी पर आए नए नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने तो इस बारे में दिखावे की रस्मों को भी ताक पर रख दिया। और अब चीन की शह और बंदूक की मदद से सत्ता में पहुंचे माओवादियों ने इस बात में किसी तरह का शुबहा नहीं छोड़ा कि वे हर मामले में भारत के खिलाफ और चीन के साथ हैं। हालांकि इस बदलाव से पहले वाली सरकारें भी चीन को खुश करने के लिए नेपाल में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को दबाकर रखती आई हैं। लेकिन नई सरकार ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों की अपीलों को दरकिनार करते हुए तिब्बती शरणार्थियों की बची खुची आजादी को छीनने का उत्साह दिखाया है वह किसी भी मायने में यह नही दिखाता कि चीन और नेपाल के संबंध बराबरी या दोस्ती वाले हैं। पिछले दिनों तिब्बती शरणार्थियों के प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जिस तरह से नेपाली पुलिस ने चीन के कूटनीतिक अधिकारियों और चीनी सुरक्षा एजेंटों को खुल्लमखुल्ला दखल देने की छूट दी उसे नेपाल के स्वतंत्र अस्तित्व का किसी भी मायने में सम्मानजनक प्रमाण नहीं माना जा सकता।

कुछ समय से जिस तेजी के साथ चीन के नेता नेपाल की यात्राओं पर आने लगे हैं और जिस तरह के प्रस्ताव नेपाली नेता उनके सामने पेश करने लगे हैं वह सब नेपाल के राट्रीय आत्मसम्मान पर चोट तो करता ही है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के नए संकेत भी देने लगा है। पिछले दिनों एक के बाद एक नेपाली नेताओं ने चीन सरकार से अनुरोध किया है कि वह ल्हासा तक आई चीनी रेलगाड़ी को काठमांडू तक ले आए। इस प्रस्ताव का चीनी नेताओं ने स्वागत किया है। चीन की मदद से नेपाल में बना सड़क तंत्र भारतीय सुरक्षा के लिए पहले से ही गंभीर खतरा बना हुआ था। और अब भारत की सीमा तक चीनी रेल का आना भारत के लिए खतरे की आखिरी घंटी है। यह खतरा और भी गहरा है क्योंकि इसके पीछे ऐसी नेपाली ताकतें हैं जो नेपाल को मानसिक रूप से चीन का उपग्रह बनाने पर तुली हुई हैं। दुर्भाग्य से यह सब तिब्बत पर चीन के कब्जे की वजह से चीन के दक्षिण एशिया में आ घुसने का ही नतीजा है।

– विजय क्रान्ति

फोटो : विजय क्रान्ति

नेपाल पर चीनी दबाव के कारण आतंक में जीते तिब्बती शरणार्थी : शरणागत की बुरी गत

तिब्बत पर चीनी नीति का पालन करने के लिए बीजिंग का नेपाल पर दबाव

नेपाल में चीनी प्रोपेगेंडा जोरों पर

काठमांडू तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मानने वाली अपनी *'एक चीन नीति'* पर नेपाल से अमल कराने के लिए बीजिंग ने नेपाल में अपने प्रतिनिधियों और प्रचार के जरिए तिब्बत अभियान तेज कर दिया है। चीनी कम्युनिश्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतरराष्ट्रीय विभाग के प्रमुख वांग जिआरुई की नेपाल यात्रा के एक पखवाड़े के भीतर ही चीन की हु नगरपालिका के प्रतिनिधि ओंग चिंग ची की अगुवाई में एक नौ सदस्यीय दल आर्थिक विकास और चीनी सहयोग पर बातचीत के सिलसिले में नेपाल पहुंचा। इसी तरह चीन के संस्कृति मंत्रालय के उपमंत्री झेंग झिंमिआओ ने नेपाल सरकार को पत्र लिखकर मार्च में नेपाल के प्रवास पर आने की इच्छा जताई है।

चीन नेपाल में दलाई लामा प्रतिनिधि कार्यालय फिर से खोलने नहीं देना चाहता। इसे चीनी दबाव में बंद कर दिया गया था। चीन अपने देश जाने के इच्छुक तिब्बतियों को नेपाल से जाने की सुविधा भी रोकना चाहता है।

पिछले हफ्ते ही चीन ने काठमांडू में तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी जिसके उद्घाटन पर चीन के राजदूत झेंग झियांग्लिन ने दावा किया था कि यह प्रदर्शनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में हाल के बरसों में हुए सामाजिक–आर्थिक विकास का ठोस प्रमाण है।

1949 में चीनी फौज ने तिब्बत पर हमला किया था। इसके दो साल बाद उसने इस देश को बीजिंग की संप्रभुता स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था। हालांकि समझौते में तिब्बत के आंतरिक मामलों में तिब्बती सरकार की स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था लेकिन उसके बाद से बीजिंग तिब्बत पर अपनी राजनीतिक व्यवस्था के साथ–साथ अपनी भाषा और संस्कृति भी थोप रहा है।

नेपाल में तिब्बत के बारे में इस चीनी प्रचार अभियान का लक्ष्य नेपाल सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ाना है कि वह नेपाल में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों की तिब्बत मुक्ति आंदोलन से जुड़ी गति विधियों पर अंकुश लगाए। ऐसी प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से चीन बाहरी दुनिया को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि तिब्बती जनता चीन के कब्जे में प्रसन्न है।

काठमांडू में हुई प्रदर्शनी में 130 तस्वीरों में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद हुई प्रगति और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने इस पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि तिब्बत ने आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में महान सफलता हासिल की है। उसने पिछले सात साल के दौरान तिब्बत के सकल घरेलू विकास में 12 फीसदी की वृद्धि दर का भी हवाला दिया।

चीनी शासन के अधीन तिब्बत में हुई प्रगति को रेखांकित करने के लिए बीजिंग सरकार ने 19–20 दिसंबर को काठमांडू में चीन–तिब्बत संस्कृति मंच का आयोजन भी किया जिसके जरिए वह तिब्बती संस्कृति को चीनी संस्कृति के हिस्से के रूप में पेश करना चाहता है। ल्हासा और काठमांडू के बीच बस सेवा को पुनर्जीवित करने के मकसद से तिब्बत का एक प्रतिनिधिमंडल नेपाल आया था। 2005 में इस बस सेवा को शुरू करने के फौरन बाद ही चीन द्वारा व्यक्तिगत यात्रियों को पर्यटक वीसा जारी करने से इंकार करने के कारण बंद कर दिया गया था।

हालांकि दोनों देशों ने पहली जनवरी से इस बस सेवा को बहाल करने के मकसद से समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि क्या वीसा व्यवस्था में कोई बदलाव किया जाएगा।

चीन नेपाल में दलाई लामा प्रतिनिधि कार्यालय फिर से खोलने नहीं देना चाहता। वह अपने देश जाने के इच्छुक तिब्बतियों को नेपाल से जाने की सुविधा भी रोकना चाहता है। चीन–नेपाल की सीमा पर चीनी फौज की मौजदूगी बढ़ रही है और तिब्बत से भाग कर आने वाले शरणार्थियो को नेपाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद चीनी सेना के हाथ सौंप देती है।

तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अ□यान की कार्यकारी निदेशक मैरी बेथ मर्की ने कहा, यह कोई गोपनीय बात नहीं रही कि चीन के सशस्त्र सुरक्षा बल तिब्बती शरणार्थियों की तलाश में नेपाल की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा सीमा पार करने में सफल रहे अनेक शरणार्थियों ने बताया है कि अतीत में उन्हें रोककर वापस भेज दिया गया था।

इटली में दलाई लामा के स्वागत से चीन सरकार की नाराज़गी

इटली के प्रधानमंत्री ने कहा दलाई लामा से मेरी मुलाकात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हुई

15 दिसंबर दुनिया भर में दलाई लामा की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान चीन सरकार ने इस बार इटली सरकार से कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। 13 दिसंबर को इटली के सांसदों के साथ दलाई लामा की मुलाकात ने बीजिंग को आगबबूला कर दिया है।

तिब्बत के पूर्व शासक और सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता को इटली के निचले सदन पार्लियामेंट चैम्बर ऑफ डेपुटिस के स्पीकर फाउस्तो बर्टिनोट्टी ने रोम स्थित मोंटेसिटोरिओ पार्लियामेंट भवन में सांसदों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इस पर चीन सरकार ने जबरदस्त नाराजगी जताई। इस नाराजगी को देखते हुए इटली सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। दलाई लामा ने मुख्य एसेंबली हॉल के बजाए उसके बगल वाले हाल में इटली के सांसदों को संबोधित किया। इस सभा में भारी संख्या में सांसदों ने भाग लिया। इनमें वहां के बहुदलीय तिब्बत समर्थक मंच के सदस्य भी शामिल थे। श्री बर्टनोट्टी के अलावा सरकार की ओर से मौजूद सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि इटली के विदेश मंत्री गियानी वर्नेटी ने दलाई लामा का गर्मजोशी से स्वागत किया।

दलाई लामा ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि वे चीन से तिब्बत के अलगाव की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि चीन ने 1951 से तिब्बत पर जबरन कब्जा किया हुआ है। दलाई लामा ने कहा कि उनका अभियान तिब्बती क्षेत्र की स्वायत्तता और वहां के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिलाए जाने के लिए है। दलाई लामा ने कहा, ''हम अपने दोनों हाथों से प्रयास कर रहे हैं। हमारा दायां हाथ हमेशा चीन सरकार तक पहुंचना चाहता है और उनसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता देने की मांग करता है। हमारा बायां हाथ इटली और दुनिया में जहां कहीं भी हमारे समर्थक मौजूद हैं उनसे मदद की गुहार लगाता है।''

उन्होंने कहा कि ''जिस दिन चीन तिब्बत की जनता को उसके अधिकार सौंप देगा हम अपना बांया हाथ हिलाकर अपने अंतरराष्ट्रीय समर्थकों का आ□ार जताएंगे और उनसे विदा ले लेंगे।'' चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ हाल ही में हुई बातचीत का हवाला देते हुए दलाई लामा ने कहा कि 2001 के बाद हुई पांच मुलाकातों में 'उल्लेखनीय प्रगति' हुई है। लेकिन पिछले साल जून–जुलाई में हुई छठी मुलाकात में चीन का कठोर हो गया। तब बीजिंग के अधिकारियों ने इस मुलाकात के बाद दावा किया कि तिब्बत का कोई मसला ही नहीं है।

हालांकि चीन सरकार इटली की सरकार से दलाई लामा की इस यात्रा के बारे में भारी विरोध व्यक्त कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इटली के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार दलाई लामा के मामले में चीन सरकार की धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है।

दलाई लामा के संबोधन के बाद विदेश मंत्री वर्नेटी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने दलाई लामा के साथ केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री रोमानो प्रोदी की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की। वर्नेटी ने कहा कि मैं एक बार फिर चीन के प्रति दलाई लामा के संतुलित व्यवहार को देखकर प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि ''दलाई लामा ने फिर दोहराया है कि वे तिब्बत की पूर्ण आजादी की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि खुले संवाद के जरिए वह तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता पाने की बात कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि दलाई लामा इटली के समर्थन की अपेक्षा कर सकते हैं। इससे पहले दलाई लामा ने 13 दिसंबर को रोम के सिटी हाल और पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव की अध्यक्षता वाले फाउंडेशन द्वारा आयोजित नोबल पुरस्कार विजेताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया था।

दलाई लामा ने अपने भाषण में मानवीय सहानुभूति की जरूरत पर जोर दिया। 1989 के शांति नोबल पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा ने कहा, ''सिर्फ कुछ अच्छे शब्दों से हालात नहीं बदल जाएंगे। बल्कि कोई भी बदलाव हमारी कार्रवाइ पर निर्भर होता है।''

इससे पहले 13 दिसंबर को चीन ने दलाई लामा की इटली यात्रा की आलोचना की थी और तब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि ''बौद्ध नेता एक राजनीतिक निर्वासित हैं और धर्म की आड़ में चीनी मातभूमि और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने वाली गतिविधियों में संलग्न हैं।''

चीन भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे दलाई लामा पर लगातार 'राष्ट्रद्रोह' के आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा मिलान में बीजिंग के वाणिज्य उच्चायुक्त ने तिब्बत के आध्यात्मिक नेता से मुलाकात की वजह से शहर के मेयर लेटिडिआ मोराट्टी की आलोचना की है।

इटली के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार दलाई लामा के मामले में चीन सरकार की धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। वर्नेटी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने दलाई लामा के साथ केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री रोमानो प्रोदी की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुलाकात की।

फोटो : विजय क्रान्ति

ल्हासा में पोताला के सामने चीनी प्रदर्शन विमान : दादागीरी का प्रदर्शन

चीन तिब्बत में अस्त्रों का जखीरा जमा करने में जुटा हुआ है

खतरे से निबटने के लिए हिमालयवर्ती जनता के हितों का ध्यान रखना जरूरी – हिमालय परिवार

14 दिसंबर 'हिमालय परिवार' ने भारत सरकार को चेताया है कि चीन सरकार जबरन कब्जाए गए तिब्बत में हथियारों को एक बड़ा जखीरा विकसित करने में लगा हुआ है जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए हिमालय परिवार की हिमाचल शाखा ने भारत सरकार को आगाह किया है कि अंततः इन हथियारों को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाना है।

हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उनके हितों का खयाल नहीं रख रही है और उन्हें सुविधाओं के साथ ही ऐसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं।

हिमालय परिवार हिमालय श्रंखला से जुड़े देशों और राज्यों का संगठन है। इसका मुख्य लक्ष्य इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच सदभाव बढ़ाना और देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। यह संगठन तिब्बत की आजादी के संघर्ष का समर्थन करता है। हिमालय परिवार (एचपी) ने चीन के समक्ष सीमा संबंधी मामलों के निपटारे का मुद्दा उठाने में भारत सरकार की नाकामी पर हैरत जताते हुए सरकार को याद दिलाया है कि जताई है 1962 में चीन भारत के खिलाफ अपनी ताकत दिखा चुका है।

उसने भारत सरकार से कहा है कि वह चीन के कब्जे से तिब्बतियों को आजाद कराने में मदद करे और इसके साथ ही उसने उससे यह बताने की भी मांग की है कि आखिर वह ऐसी मदद देने में क्यों हिचक रही है। अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने के वास्ते हिमालय परिवार ने जम्मू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का भी आयोजन किया जिसमें उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए लेह–मानसरोवर मार्ग को खोलने और भोटी भाशा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की।

संगठन ने एक संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित किया जिसमें हिमालय परिवार (लद्दाख) के अध्यक्ष ताशी तारगिस, अनिल कुमार और वीणा हांडा ने इस मुद्दे को सुलझाने में हीला हवाला करने के कारण केंद्र सरकार की आलोचना की।

भोटी भाषा को आठवीं अनसूची में शामिल किए जाने और लद्दाख से होकर कैलाश–मानसरोवर मार्ग शुरू करने की अपनी मांगों पर जोर देते हुए हिमालय परिवार के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे।

परिवार के नेताओं ने कहा कि कैलाश–मानसरोवर हिंदुओं का प्राचीन तीर्थ स्थल है इसलिए भारत सरकार को लद्दाख से होकर गुजरने वाले इस मार्ग को खोलने का मुद्दा चीन की सरकार के सामने उठाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उनके हितों का खयाल नहीं रख रही है। और उन्हें सुविधाओं के साथ ही ऐसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने सरकार पर हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति भेदभाव वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी मांगों पर फौरन अमल किया जाए क्योंकि भारत की रक्षा के मामले में हिमालयवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय देश की रक्षा की पहली ढाल हैं।

'विश्व के नक्शे पर तिब्बत' अ□यान की शुरुआत

फ्रैंड ऑफ टिबेट ने नक्शा जारी किया

10 दिसंबर मुंबई विश्व मानवाधिकार दिवस को मुंबई में दुनिया के ऐसे मानचित्र का अनावरण किया गया जिसमें तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्शाया गया है। 'वर्ल्ड मैप विद तिब्बत' की पहली प्रति परमपावन दलाई लामा के अधिकृत अनुवादक और धर्मशाला स्थित तिब्बती लाइब्रेरी और आर्काइव के निदेशक गेशे ल्हाकदोर ने जारी की। उन्होंने तिब्बत को एक अलग देश के रूप में दर्शाने वाले मानचित्र को जनता को सौंपते हुए कहा

कि तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद उसे विश्व मानचित्र से हटा कर चीन ने भले ही दुनिया को कुछ समय के लिए धोखा दिया है पर यह जाग्रत हो रहे विश्व में अब यह धोखा बहुत समय तक नहीं चल सकता। उन्होंने बताया कि चीनी आक्रमण की वजह से पांच दशकं पहले उन जैसे हजारों तिब्बतियों को अपने देश से बाहर भागना पड़ा था।

यह अभियान और चीन अधिकृत तिब्बत को फिर से स्वतंत्र देश के रूप में दर्शाने वाला मानचित्र मुंबई स्थित फ्रैंड ऑफ तिब्बत कैंपेन से जुड़े रोहित सिंह के दिमाग की उपज है। उन्होंने इसे तैयार करने के लिए काफी अनुसंधान किया।

संगठन के संस्थापक श्री सेतु दास ने इस मानचित्र को हर तिब्बती का सपना बताया। उन्होंने कहा, श्यह चीनी आधिपत्य के अधीन रह रहे और संघर्ष कर रहे 60 लाख तिब्बतियों का सपना है और रोहित सिंह जैसे लोगों का भी सपना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन यह सपना हकीकत में बदल जाएगा।

रोहित सिंह ने वहां मौजूद तिब्बती और भारतीय लोगों को विश्व मानचित्र में तिब्बत की उपस्थिति के महत्व को बताया। उन्होंने कहा, कोई भी देश अपनी सीमाओं और राजनीतिक मानचित्र में अपनी मौजूदगी से पहचाना जाता है। चीन के कब्जा करने से पहले तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था लेकिन कब्जा होने के बाद यह विश्व मानचित्र से गायब हो गया। यह प्रयास विश्व मानचित्र में तिब्बत को फिर से स्थापित करने और इसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए है जिसे चीन नष्ट करना चाहता है। रोहित सिंह ने बताया कि उनका संगठन जल्द ही राष्ट्रव्यापी शैक्षणिक जागरुकता अभियान चलाएगा।

फ्रैंड्स ऑफ तिब्बत एक जनांदोलन है जिसका लक्ष्य तिब्बत के मसले को जिंदा रखना है। इसकी गतिविधियों का लक्ष्य स्वत्रंता के लिए संघर्ष कर रहे तिब्बतियों को समर्थन देते हुए चीनी अधिग्रहण को खत्म करना है।

काग्यू संप्रदाय का बोधगया में उत्सव

बोधगया, 19 दिसंबरः 17वें कर्मापा उग्येन त्रिनले दोरजी की अगुवाई में सोमवार को अनेक बौद्ध भिक्षुकों और श्रद्धालुओं ने 25वें अंतरराष्ट्रीय काग्यू मोनलम प्रार्थना महोत्सव के पहले दिन विश्व शांति और सदभाव के लिए प्रार्थना की।

बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में प्रार्थना सभा के लिए दुनिया भर से आए 7 हजार बौद्ध भिक्षुक, भिक्षुणियां और श्रद्धालु एकत्र हुए थे। इस तरह की

काग्यू पा के गुरू कर्मा पा जी परमपावन दलाई लामा के साथ : राष्ट्र धर्म का बंधन

पहली सभा 1983 में हुई थी। 8 दिवसीय यह उत्सव दुनिया□र में शांति, सदभाव और आनंद की स्थापना के लिए आयोजित किया जाता है। कहा जाता है कि तिब्बत में 500 साल पहले काग्यू संप्रदाय द्वारा इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। तिब्बती बौद्धमत के चार संप्रदायों में से यह एक है। 17वें कर्मापा और कर्मापा काग्यू संप्रदाय के प्रमुख उग्येन त्रिनले दोरजी के सचिव डोम्पो सेरिंग ने कहा कि काग्यू मोनलाम में सबसे बड़ी चिंता पर्यावरण सुरक्षा को लेकर है।

श्री सेरिंग ने कहा, हर जीवधारी को आपस में शांति और सद्भ□ाव के साथ रहना चाहिए। और आज के पर्यावरण में गुरुजी (कर्मापा) महसूस करते हैं कि श्हमें सबसे ज्यादा ध्यान पर्यावरण पर देना चाहिए। यह एक अंडे की तरह है, यदि हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वह टूट जाएगा और पूरी तरह नष्ट हो जाएगा।श

तिब्बत के काग्यू बौद्ध पदानुक्रम में सर्वोच्च लामा कर्मापा ही ऐसे वरिष्ठ भिक्षु हैं जिन्हें बीजिंग और निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा दोनों ने ही मान्यता दी है।

प्रार्थना समारोह में अर्जेंटीना से भाग लेने आई एक श्रद्धालु सान्द्रेइया ने कहा, श्मैं यहां पहली बार आई हूं लेकिन मैं देख सकती हूं कि यहां बहुत ऊर्जा है। हम शांति और अध्यात्मिकता के प्रति लोगों की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यहां अलग–अलग जगहों और अलग–अलग भावनाओं वाले लोग यहां आए हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि वे सब शांति चाहते हैं।

रोहित सिंह कहा, कोई भी देश अपनी सीमाओं और राजनीतिक मानचित्र में अपनी मौजूदगी से पहचाना जाता है। चीन के कब्जा करने से पहले तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था लेकिन कब्जा होने के बाद यह विश्व मानचित्र से गायब हो गया। यह प्रयास विश्व मानचित्र में तिब्बत को फिर से स्थापित करने के लिए है।

फोटो : विजय क्रान्ति

ल्हासा के ड्रेपुंग मठ के एक मंदिर में माओ की तस्वीर : सांस्कृतिक संहार

दलाई लामा ने चीन पर 'सांस्कृतिक संहार' का आरोप लगाया

चीन की ओर से रचनात्मक जवाब नहीं मिल रहा

18 दिसंबर, बर्लिन जर्मन की एक राजनीतिक पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित साक्षात्कार में दलाई लामा ने चीन पर 'सांस्कृतिक संहार' का आरोप लगाया है। 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहे तिब्बती शासक और धार्मिक नेता दलाई लामा ने कहा कि आधुनिकता के नाम पर ल्हासा को एक चीनी शहर में तब्दील कर दिया गया है।

दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों से उनको इस बात की जानकारी मिलती रहती है कि चीन उनके देश के ऊपर अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाता जा रहा है। तिब्बत में एक प्रकार का सांस्कृतिक नरसंहार बहुत तेजी से हो रहा है।

जर्मन चांसलर सुश्री एजेंला मर्केल के साथ उनकी मुलाकात के बाद जर्मन–चीन संबंधों में आई बाधा पर दलाई लामा ने कहा कि उन्हें इसका दुख है। दलाई लामा ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने विश्व के राजनितिज्ञों में यह रुचिकर रूझन देखा है कि जब वे कोई गैरसरकारी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं तो उनसे मिलने को बेताब रहते हैं। लेकिन एक बार सरकारी जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद वह चीन से दुश्मनी पालने से कतराने लगते हैं।

दलाई लामा ने कहा कि वह एक लंबे अरसे से तिब्बत से बाहर रह रहे हैं। लेकिन वहां से आने वाले शरणार्थियों से उनको इस बात की जानकारी मिलती रहती है कि चीन उनके देश के ऊपर अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाता जा रहा है। कई तिब्बती तो अपनी मातृभाषा तक को भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन सरकार को इस बात की जानकारी है या नहीं लेकिन तिब्बत में एक प्रकार का सांस्कृतिक नरसंहार बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को गंभीर खतरा है। बंजारों को आधुनिकीकरण के नाम पर आधुनिक गांवों में जबरन बसाया जा रहा है। दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत की पहचान को नष्ट होने से बचाने के लिए वह चीनी व्यवस्था के भीतर स्वायत्तता के लिए तैयार हैं। बशर्ते यह स्वायत्तता वास्तविक हो। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके प्रस्ताव पर चीन की ओर कोई प्रोत्साहन भरा उत्तर नहीं मिला है।

ऑकलैंड में वैश्विक मानवाधिकार मशाल जलाई गई

15 दिसंबर न्यूज़ीलैंड में सेंट्रल ऑकलैंड के क्वीन सेंट के मध्य में स्थानीय नागरिकों ने दो ग्रीक देवियों और सात मशालों के साथ तिब्बत के समर्थन में एक मौन जुलूस निकाला। इन लोगों का कहना है कि यदि चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी रहता है तो बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार किया जाना चाहिए।

स्थानीय लोगों के लिए यह जुलूस एक अनूठा अनुभव था। इसमें ऑकलैंड में रहने वाले तिब्बती समुदाय, श्रीलंका और बर्मा के बौद्ध, चीन के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता, फालुन गोंग के उत्पीड़न की जांच की मांग करने वाले गठबंधन (सीआइपीएजी) और कई जागरुक नागरिक शामिल थे।

ऑकलैंड न्यूजीलैंड के उन 16 शहरों में प्रथम है जहां से होकर वैश्विक मानवाधिकार मषाल रैली निकाली गई। यह मशाल 25 देशों के 130 शहरों से होकर गुजरेगी। ऑकलैंड सिटी काउंसलर और सीआइपीएजी की सदस्य डॉ कैथी केसी ने मशाल की न्यूजीलैंड यात्रा की शुरुआत करते हुए मशाल थामी। डॉ कैथी ने कहा कि यह मशाल चीनी लोगों खासतौर से फालुन गोंग समुदाय के लोगों की पीड़ा के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा, यह सांकेतिक मशाल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी पीड़ितों के प्रतीक के रूप में जल रही है। डॉ केसी फालुन गोंग संप्रदाय के लोगों के जीवन पर अंकुश लगाने वाले चीनी सरकारी प्रतिबंधों की जांच के संद□ में तैयार की गई रिपोर्ट के सह लेखक रेवरेंड डेविड किलगोर और सीआइपीएफजी से जुड़ी हैं।

डॉ केसी ने बताया कि चीन में राजनीतिक कारणों से लोगों को मुत्युदंड देने के बाद उनके अंग निकाल लिए जाते हैं। बाद में इन अंगों का प्रत्यारोपण के लिए व्यापार किया जाता है। दो साल पहले उन्हें जब अपनी एक किडनी प्रत्यारोपित करवानी पड़ी थी उस दौरान उन्हें पता लगा था कि किडनी प्रत्यारोण के लिए दूसरे देशों के लोग

आखिर चीन क्यों जाते हैं। डॉ केसी ने कहा, ''चीन सरकार आपको कभी यह नहीं बताएगी कि प्रत्यारोपण के लिए दिए जा रहे अंग फालुन दाफा समुदाय के सदस्यों को मौत की सजा देने से प्राप्त किए गए हैं।'

उन्होंने कहा कि चीन को अंग प्रत्यारोपण के कारोबार से जुड़े आरोपों के मद्देनजर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों को अपने देश में आकर इस बात की जांच की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन चीन सरकार ने एमनेस्टी के चीन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है।

इंडोनेशियाई मानवाधिकार आयोग की मैरी लीडबेटर ने कहा कि यदि फालुन गोंग, बर्मा के लोग, दारफुर और तिब्बत के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो सभी लोगों को इससे फायदा होगा। उन्होंने कहा, यहां हम मानवाधिकारों की दिशा में कोई प्रगति इसलिए नहीं कर सके क्योंकि हम सबने मिलकर काम नहीं किया। सुश्री लीडबेटर ने कहा कि ओलंपिक के लिए चीन का नारा एक चीन–एक सपना, उचित नहीं है क्योंकि खेलों के नजदीक आने के बावजूद चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले जारी हैं।

ताईवानी समुदाय के प्रतिनिधि गुई सेंग यांग ने कहा कि चीन को ओलंपिक खेलों की मेजबानी की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ''क्या आप जानते हैं कि चीन में बने प्रत्येक स्टेडियम के लिए कितने लोगों को अपने घरों को खोना पड़ा? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बिना किसी मुआवजे के अपने घर खो दिए।''

ग्रीन पार्टी के सांसद केथ लाक ने कहा कि कम्युनिस्ट चीन में मानवाधिकार हनन से पीड़ित हर समुदाय के लिए इस मशाल रैली का महत्व है। उन्होंने कहा, ''यह स्वतंत्रता की रैली है। और यह केवल चीन की जनता के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है।'' ग्रीन पार्टी के सांसद नांदोर तानक्जोस ने रविवार को ऑकलैंड के उत्सव के बाद हैमिल्टन पहुंची मानवाधिकार मशाल रैली का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार ने चीन में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार का आश्वासन दिया था लेकिन वास्तव में असंतुष्टों का उत्पीड़न बढ़ा है।

उन्होंने कहा, हमें बीजिंग की सरकार को यह दिखाना होगा कि अपने इस 'सफाई अभियान' से वह दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकती। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, ''हम चीन में सभी लोगों के लिए मानवाधिकारों की मांग करते हैं और इस पर तुरंत अमल चाहते हैं।''

सेरिंग और उनके चीनी लेखक पति जिनली अपनी पुस्तक के मुखपृष्ठ पर : साथ–साथ

तिब्बती लेखिका सेरिंग वोज़ेर को नॉर्वे का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पुरस्कार

सरकारी दमन के बावजूद साहस दिखाया

17 दिसंबर नॉर्वेजियन ऑथर्स यूनियन ने 2007 का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पुरस्कार चीन में रह रही तिब्बती लेखिका सेरिंग वोज़ेर को दिया है। नार्वे में तिब्बत कमेटी की अध्यक्ष चुंगदाक कोरेन कहती हैं, ''हमें खुशी है कि तिब्बती लेखिका वोज़ेर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।''

नॉर्वेजियन ऑथर्स यूनियन इस बात से सहमत थी कि वर्ष 2007 का पुरस्कार देने के लिए वोज़ेर एकदम उपयुक्त पात्र हैं क्योंकि चीन सरकार द्वारा उनके लेखन को घोर आपत्तिजनक पाए जाने के बावजूद उन्होंने उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी किताबों को प्रकाशन जारी रखा। इसके साथ ही उन्होंने अपने लेखों और ब्लॉगों के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया है। उन्होंने चीनी दमन और तिब्बत के औपनिवेशीकरण पर भी लेखन किया है।

2003 में उनकी पुस्तक 'डायरी ऑफ तिब्बत' के प्रकाशन के बाद वोज़ेर को ल्हासा छोड़ना पड़ा और उनकी किताब को चीनी शासन ने प्रतिबंधित कर दिया। वह चीन में ब्लॉगर्स की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा वे इंटरनेट का प्रयोग कर सूचना तंत्र पर सरकारी तानाशाही को भी चुनौती देती हैं। पुरस्कार के तहत एक लाख क्रोनर और एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। रेडियो ताइवान इंटरनेशनल को दिए साक्षात्कार में वोसर ने कहा कि इस पुरस्कार से पता चलता है कि तिब्बत की परिस्थितियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है।

2003 में उनकी पुस्तक 'डायरी ऑफ तिब्बत' के प्रकाशन के बाद वोज़ेर को ल्हासा छोड़ना पड़ा और उनकी किताब को चीनी शासन ने प्रतिबंधित कर दिया। वह चीन में इंटरनेट का प्रयोग कर सूचना तंत्र पर सरकारी तानाशाही को भी चुनौती देती हैं।

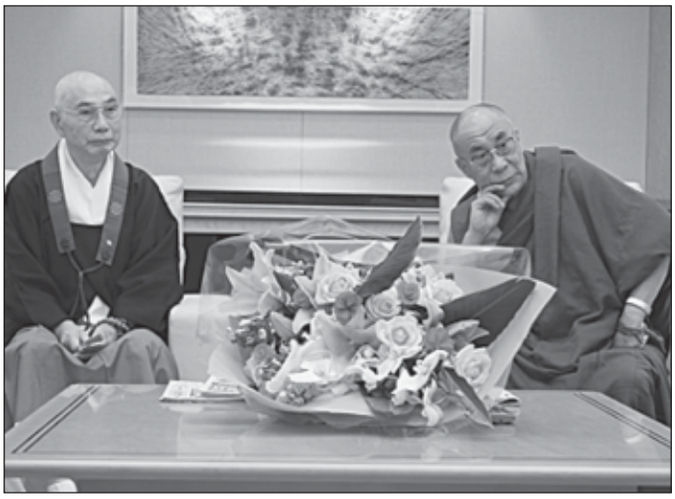

कैमरे की अ

1. जापान यात्रा के दौरान कानागावा बौद्ध फैडरेशन के अध्यक्ष माननीय रुइयो
2. 14 नवंबर के दिन दलाई लामा जी ने दिल्ली में आदरणीय एल एस प्रियदर्श
3. 13 दिसंबर को रोम यात्रा के दौरान दलाई लामा जी का वहां के मेयर वाल्ट
4. नई दिल्ली में जैन संप्रदाय के अहिंसा पर्यावरण साधना मंदिर के उद्घाटन
5. विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर 10 दिसंबर को नई दिल्ली की विशा
6. नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी की फोटो प्रतियोगिता में ज्यां क्लोद लुई के इ
7. 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर शुरू हुई 365 किमी लंबी पदयात्रा क
8. संयुक्त राष्ट्र की चीन और ओलंपिक नीतियों के खिलाफ न्यूयार्क में तिब्बती यु
9. दलाई लामा के चित्र पर चीनी प्रतिबंध के बावजूद तिब्बत के एक स्थान पर
10. 15 दिसंबर को सानफ्रांसिस्को में मनाए गए 'तिब्बत दिवस' के मौके पर तिब

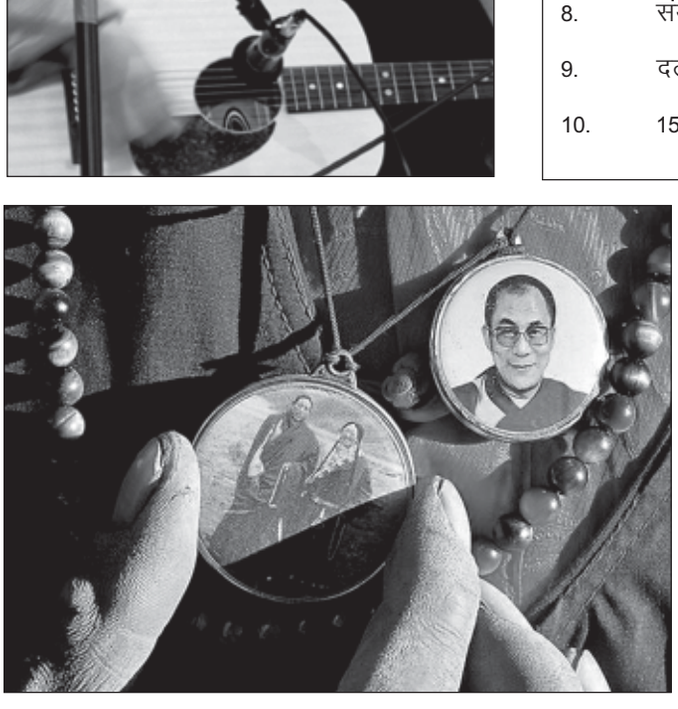

♦ आंखों देखी

की आंख से

य रुइयो कुराता ने दलाई लामा जी का स्वागत किया।

स प्रियदर्शी और श्रीमती शीला दीक्षित के साथ विश्व शांति स्तूप का अनावरण किया।

मेयर वाल्टर वेलत्रोनी ने स्वागत किया।

उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ जैन गुरुओं के साथ दलाई लामा जी ने भाग लिया।

की विशाल रैली में तिब्बत समर्थकों ने उत्साह से भाग लिया।

लुई के इस फोटो को पहला पुरस्कार मिला जिसमें शीशे से झांकते दो तिब्बती बच्चे हैं।

पदयात्रा को तिब्बती भिक्षु–भिक्षुणियों ने 31 दिसंबर को चेन्नै में पूरा किया।

तिब्बती युवा कांग्रेस, स्टूडेंट्स फार फ्री टिबेट और यूएस टिबेट कमेटी ने प्रदर्शन किया।

स्थान पर अपने चोगे में उनके चित्र वाले बैज लगाए एक तिब्बती।

के पर तिब्बती युवा गायक तेंचू ने लोगों का दिल जीत लिया।

विवादास्पद चीनी बांध को अब तिब्बत में बनाया जाएगा

चीनी अधिकारी अब यांग्त्सी नदी के विवादास्पद बांध को तिब्बती क्षेत्र में ले जाने पर विचार कर रहे हैं

स्थानीय स्तर पर होने वाले विरोध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जताई जा रही चिंता की वजह से यांग्त्सी नदी की टाइगर लीपिंग गोर्ज पर बांध बनाने की विवादास्पद योजना को खत्म करने का संकेत दिया है। अब सरकार का इरादा इस बांध को 200 किमी दूर तिब्बत बहुल इलाके में बनाने का है।

21 दिसंबर चीन के युन्नान प्रांत की सरकार ने स्थानीय स्तर पर होने वाले विरोध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जताई जा रही चिंता की वजह से यांग्त्सी नदी की *टाइगर लीपिंग गोर्ज* पर बांध बनाने की विवादास्पद योजना को खत्म करने का संकेत दिया है। अब सरकार का इरादा इस बांध को 200 किमी दूर तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र देचेन के वेइक्सी और देचेन काउंटियों की सीमाओं से लगे तिब्बती बहुल इलाके में बनाने का है।

इस परियोजना के विषय पर लंबी चुप्पी के बाद प्रांतीय सरकार अब इस फैसले पर पहुंची है कि दुनिया के सबसे गहरे पहाड़ी खड्ड में गिने जाने वाले इस खड्ड से कोई बांध नहीं बन सकता। इस खड्ड को एक विश्व विरासत भी माना जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट ने तीन दिन पहले यह बताया था कि अब इस इलाके के बजाए बांध का निर्माण तीन विकल्पों में से होना है। अखबार के अनुसार देचेन के चुनाव की संभावना ज्यादा है। उम्मीद है कि बांध की वजह से करीब 20 हजार लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापित होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा तिब्बती होंगे।

देचेन चीन के सिचुआन प्रांत में है और यह तिब्बत के खम प्रांत का एक प्रमुख इलाका है। 1951 में तिब्बत को जबरन चीन में शामिल करने के बाद चीन सरकार ने तिब्बत के तीन प्रांतों में से दो प्रांतों खम और आम्दो को तिब्बत से काट कर अलग कर दिया था और इनके हिस्सों को आसपास के चीन प्रांतों युन्नान, सिचुआन, चिंघाई और गांसू में मिला दिया गया था। उस समय पूरे तिब्बत की जनसंख्या लगभग 60 लाख थी। पिछले पचास साल के दौरान इन प्रांतों में दूसरे चीनी प्रांतों से लाकर भारी संख्या में हान चीनियों को बसाया गया है। 2002 के आधिकारिक चीनी जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार इन चार प्रांतों की कुल जनसंख्या लगभग 15 करोड़ थी। इसमें से स्थानीय तिब्बतियों की संख्या केवल 35 लाख थी।

मार्निंग पोस्ट के अनुसार बांध की विवादास्पद योजना को टाल देने से उन ग्रामीणों ने राहत महसूस की है जिन्होंने चीन के ताकतवर बिजली निर्माताओं और स्थानीय अधिकारियों का विरोध किया था। समाचार में कहा गया है कि इन ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया है।

ग्रामीणों द्वारा इस बांध का विरोध 2004 से हो रहा था और इस विरोध के तहत नागरिकों ने पिछले साल बीजिंग सरकार को एक याचिका भी भेजी थी।

टाइगर लीपिंग गोर्ज बांध परियोजना के लिए शांगरी–ला और युलुंग काउंटी के लगभग एक लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ता। इनमें एक बड़ा अनुपात वहां के अल्पसंख्यक लोगों का है। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण 2004 में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इस 276 मीटर ऊंचे बांध से सालाना 88.3 अरब किलोवाट बिजली पैदा होने की उम्मीद थी। लेकिन इस परियोजना का असली लक्ष्य यांग्त्सी नदी के पानी को मोड़कर चीन के उन इलाकों में ले जाना है जहां पानी की भारी किल्लत है। लेकिन इससे यांग्त्सी के प्राकृतिक रास्ते पर पड़ने वाले इलाकों पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका से इस परियोजना का विरोध हो रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित बांध पर जारी लंबी बहस में कहा गया कि इस बांध से स्थानीय अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन यापन में गंभीर बाधा आ सकती है। इस प्रस्तावित परियोजना में तीन खड्डों पर बनने वाले बांध और दक्षिण–उत्तर पानी स्थानांतरण परियोजना भी शामिल हैं और ये दोनों पर्यावरण को भारी नुक्सान पहुंचा सकते हैं। इनकी वजह से हजारों सांस्कृतिक विरासतों को भी ढहाना पड़ सकता है.

मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की केंद्रीय सरकार ने दर्रे को लेकर जानबूझकर विवादास्पद कदम उठाया बावजूद जबकि वह इसकी

वजह से स्थानीय पर्यावरण और जातीय अल्पसंख्यकों की अनूठी संस्कृति को होने वाले भरपाई न किए जाने वाले नुक्सान से अच्छी तरह वाकिफ थी।

अखबार के अनुसार, शविवादास्पद परियोजना की रिपोर्टिंग को लेकर बीते दो साल से चुप्पी साधे बैठे स्थानीय मीडिया से कहा गया है कि वह बांध के प्रस्ताव को टालने वाली खबर की रिपोर्ट प्रकाशित न करे।इ

बीजिंग सरकार ने एसएमएस संदेशों से डर कर रोक लगाई

बीजिंगः 24 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चाइना ह्यूमन राइटस डिफेंडर ने बीजिंग शहर में ऐसे लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बताया है जो एक दूसरे को मोबाइल एसएमएस के रास्ते समाचार भेजते हैं। चीन सरकार ने ऐसे टेक्स्ट संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो उसकी राय में 'अफवाहें फैलाने' का काम कर रहे हैं या फिर जिनसे 'सार्वजनिक सुरक्षा' को खतरा है।

समूह ने एक बयान में कहा कि रोजाना औसतन 18 करोड़ एसएमएस भेजे जाते हैं और ये टेक्स्ट मैसेज मुख्य धारा की मीडिया में नदारद समाचारों को हासिल करने का महत्वपूर्ण जरिया हैं।

2008 के ओलंपिक खेलों ने, जिनकी मेजबानी बीजिंग कर रहा है, प्रदर्शनकारियों को चीन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और तिब्बत की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी प्रकट करने का एक बड़ा मौका उपलब्ध कराया है। नागरिक प्रशासन विभाग ने पिछले महीने अपनी वेब साइट पर जारी किए गए नोटिस में कहा है कि बीजिंग की पुलिस सरकारी एजेंसियों और दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर जांच करेगी और उन लोगों को दंड देगी जो एसएमएस का इस्तेमाल 'अफवाह फैलाने' और 'सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा' उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं।

चीनी अधिकारी आमतौर पर अस्पष्ट आरोपों की आड़ में राजनीतिक असंतुष्टों और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं जिनसे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा है।

हालांकि नोटिस में इस विशिष्ट सजा का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इसी साल कुछ समय पहले शहर की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र बीजिंग डेली में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं या गलत सूचनाएं दे रहे हैं उन्हें कम से कम 10 दिन की जेल हो सकती

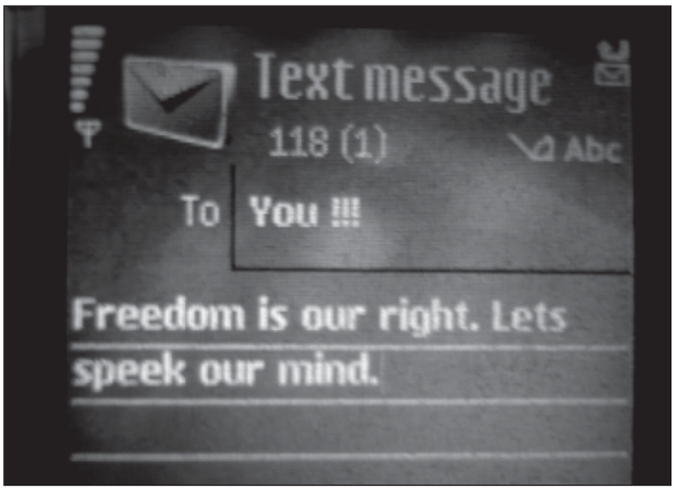

एस एम एस की ताकत से डरता है चीन : जनमत की ताकत

है और उन पर 500 युआन का जुर्माना हो सकता है।

चीन में 50 करोड़ से ज्यादा सेलफोन उप□ाक्ता हैं और एसएमएस सभाओं या प्रदर्शनों की सूचना देने का प्रभावी तरीका बन गए हैं। इस साल गर्मियों में दक्षिणी तटीय शहर झियामेन में एक केमिकल प्लांट के निर्माण की योजना को यहां के निवासियों द्वारा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजे गए 10 लाख एसएमएस के बाद टाल दी गई थी। इन संदेशों में उन्होंने स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान की आशंका जताते हुए सरकार से इस परियोजना को रोकने का आग्रह किया गया था।

इस बीच इसी महीने तिब्बती □ाषा के एक ऑन लाइन डिस्कशन फोरम को सरकारी वेब साइट पर लगे नोटिस के मुताबिक बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें 'चीनी कानूनों का उल्लंघन करने वाली सामग्री' थी। वेब साइट में लगी एक नोटिस के मुताबिक www.Tibet123.com को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें 'गैरकानूनी सामग्री' थी।

नोटिस में कहा गया कि ''वह इन सड़ी–गली' प्रविष्टियों की आलोचना करती है जिनमें ऐसी नुक्सानदेह सामग्री प्रकाशित की गई है''। इसके साथ ही नोटिस में लोगों से टिप्पणी देने की अपील भी की गई। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह नोटिस मॉडरेटर की ओर से जारी किया गया या सरकार की ओर से.

मीडिया के अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इस साइट को तिब्बतियों से संबंधित नेटस्पेस पर सबसे सक्रिय मंच बताया था जिसके 6200 पंजीबद्ध सदस्य थे। पेरिस स्थित यह फोरम 6 दिसंबर से बंद है।

चीन में 50 करोड़ से ज्यादा सेलफोन उप□ाक्ता हैं और एसएमएस सभाओं या प्रदर्शनों की सूचना देने का प्रभावी तरीका बन गए हैं। इस साल झियामेन में एक केमिकल प्लांट के निर्माण की योजना को यहां के निवासियों द्वारा अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजे गए 10 लाख एसएमएस के बाद टाल दी गई थी।

चीनी सेना की कार्रवाई में भिक्षुओं की गिरफ्तार के बाद जेशो बैकर मठ बंद

''चीन को न भिक्षुओं की जरूरत है और न मठ की'' – चीनी अधिकारियों का जवाब

20 दिसंबर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में चीनी अधिकारियों ने दो और भिक्षुकों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने स्थानीय लोगों और सशस्त्र पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद चलाए गए सरकारी राजनीतिक शिक्षा आ□यान में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था। इस अभियान के तहत उन तिब्बती नागरिकों को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है जो चीन सरकार के इशारों पर चलने से इनकार कर रहे हैं।

तिब्बत के नागचू क्षेत्र के जेशो बैकर मठ के एक भिक्षु ने एक साक्षात्कार में बताया कि श्दो भिक्षुओं नेनिंग और तारफेल को हाल ही में पकड़ा गया।श उसने बताया कि, शभिक्षुओं को दलाई लामा की आलोचना का साथ देने और उनके खिलाफ जारी किए गए बयान पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। उन्हें बता दिया गया कि यदि कोई इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इंकार करेगा तो उसे 10 हज़ार युआन जुर्माना भरना होगा। लेकिन दोनों भिक्षुकों ने दलाई लामा की आलोचना करने से दो टूक इंकार कर दिया और कहा कि उनके पास 10 हजार युआन भी नहीं हैं। इसके बाद उन्हें अलग ले जाया गया और तब से किसी को यह पता नहीं कि आखिर उन्हें कहां रखा गया है।''

बैकर में नवंबर में एक दुकानदार से विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए छह भिक्षुओं की रिहाई की मांग को लेकर भारी प्रदर्शन हुए थे जिन पर काबू पाने के लिए चीनी सुरक्षा बलों ने भारी बल प्रयोग किया था। तिब्बतियों के साथ हुए संघर्ष के बाद सैकड़ों सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को इस इलाके में तैनात कर दिया गया। दुकानदार के साथ हुए विवाद में उपरोक्त दो किशोर भिक्षुकों को भी पकड़ा गया था।

जिन अन्य लोगों को पकड़ा गया उनकी शिनाख्त केयू, दामदुल, दोरजी दाकपा और ताशी के रूप में की गई। लेकिन एक भिक्षु की पहचान नहीं हो सकी। इन सबको अज्ञात स्थान पर रखा गया है। क्षेत्र में मौजूद सूत्रों ने रेडियो फ्री एशिया की तिब्बती सेवा को बताया कि किशोरवय भिक्षुओं 15 वर्षीय येशी तोकमे और 16 वर्षीय धोंदपु दोरजी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों को डराने के लिए फायरिंग की।

इन घटनाओं के बाद इस क्षेत्र में लोगों के बीच 'देशभक्ति की शिक्षा' का प्रचार शुरू किया गया जिसका लक्ष्य लोगों को यह समझाना है कि वे अपनी तिब्बती पहचान को दरकिनार करके अच्छे चीनी नागरिक बनने की ओर ध्यान दें। 'देशभक्ति' के नाम पर दी जाने वाली इस शिक्षा में दलाई लामा को चीन को विभाजित करने वाला 'देशद्रोही' बताया जाता है और लोगों को जबरन ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनमें दलाई लामा की आलोचना शामिल होती है।

बैकर के भिक्षु ने कहा, ''स्थानीय तिब्बतियों और भिक्षुकों ने चीनी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे उन्हें बंदी लोगों से मिलने और स्थानीय मठ को खोलने की इजाजत दें। लेकिन चीनी अधिकारियों ने तिब्बतियों से कहा कि सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किए गए लोगों को पकड़ कर रखने और उन्हें दंड देने का अधिकार दिया गया है। इसलिए अगर कोई भी उनके समर्थन में खड़ा होगा तो घटना के लिए वह भी जिम्मेदार माना जाएगा''। रेडियो फ्री एशिया ने स्थानीय अधिकारियों से उनकी राय जानने का प्रयास किया लेकिन अधिकारियों से उनकी बात नहीं हो पायी।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद से मठ सुनसान पड़ा हुआ है। मठ में पहले काम कर चुके एक तिब्बती ने कहा, ''बैकर में तिब्बतियों और हान अधिकारियों के बीच हुए संघर्ष के बाद जांचकर्ताओं और अधिकारियों के दबाव में अधिकांश भिक्षु मठ को छोड़कर अपने घरों की ओर चले गए हैं जिस कारण मठ खाली पड़ा है।''

मठ के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, ''वहां आमतौर पर 200 भिक्षुक रहते थे। 7 दिसंबर को 34 तिब्बतियों का एक समूह चीनी अधिकारियों के पास गया था और उनसे उन्होंने बंदी लोगों की रिहाई और मठ में नियमित कामकाज शुरू करने की इजाजत देने का आग्रह किया था। लेकिन इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा कि ''न तो बैकर को और न ही चीन को भिक्षुओं या मठ की जरूरत है।''

इस तिब्बती ने बताया कि बैकर मठ के बंद होने से स्थानीय तिब्बती मायूस हो गए हैं। इस मठ की शुरूआत जो रिंपोछे के अनुयायी जे नेनतेन नीमा ने की थी। इस घटना के बाद इस क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है क्योंकि चीनी अधिकारियों नेकड़ा रुख अपनाया हुआ है।

लोगों के बीच 'देशभक्ति की शिक्षा' का प्रचार शुरू किया गया जिसका लक्ष्य लोगों को यह समझाना है कि वे अपनी तिब्बती पहचान को दरकिनार करके अच्छे चीनी नागरिक बनने की ओर ध्यान दें। 'देशभक्ति' के नाम पर दी जाने वाली इस शिक्षा में लोगों को जबरन ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है जिनमें दलाई लामा की आलोचना शामिल होती है।

ब्रिटिश संसद में तिब्बत में मानवाधिकारों की हालत पर बहस

सरकार ने आश्वासन दिया कि तिब्बत की हालत पर नजर रखी जा रही है

लंदन, 8 जनवरी ब्रिटेन की संसद हाऊस ऑफ कॉमन्स में 8 जनवरी को हुई बहस के दौरान लेविस से लिबरल डेमोक्रैटिक सांसद श्री नॉर्मन बेकर ने तिब्बत में मानवाधिकारों की हालत पर सवाल उठाया। उनके सवाल से वहां एक गंभीर चर्चा शुरू हुई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह सवाल पूछा कि चीन ने अपने यहां, खासकर अपने कब्जे वाले तिब्बत में, मानवाधिकारों और प्रेस की आजादी का सम्मान करने का जो वायदा किया है, उसे निभाने के लिए चीन सरकार को प्रोत्साहित करने के वास्ते वह किस तरह के कदम उठा रही हैं।

उनके इस सवाल के जवाब में विदेश एवं राष्ट्रमंडल मानवाधिकार कार्यालय (चीन) संबंधी मामलों (एफसीओ) के मंत्री सुश्री मेग मन्न ने कहा, ''हमने तिब्बत सहित समूचे चीन में मानवाधिकारों के सम्मान के लिए चीन सरकार को प्रोत्साहित किया है। विदेश सचिव ने मानवाधिकार के मुद्दे को चीन के विदेश मंत्री के साथ दिसम्बर में हुई बातचीत के दौरान उठाया था। लंदन ओलम्पिक मामलों की मंत्री ने भी गत नवम्बर में मीडिया को स्वतंत्रता देने का मुद्दा चीन सरकार के समक्ष रखा था। बीजिंग में मानवाधिकारों के सिलसिले में ब्रिटेन और चीन के बीच इस माह के अंत में होने वाली अगले दौर की बातचीत में भी तिब्बत को लेकर हम अपनी चिंताओं से चीन सरकार को अवगत कराएंगे।''

इस पर श्री नॉर्मन बेकर ने प्रश्न किया, ''चीन ने अपने यहां विदेशी पत्रकारों को आजादी देने का वायदा तो किया है, लेकिन उसने अधिकृत तिब्बत में मीडिया पर लगाम और कस दी है। उन्होंने चीनी जेलों और बंदीगृहों तक रेड क्रॉस को पहुंचने देने का वादा तो किया है, लेकिन इस वादे से तिब्बत को अलग रखा है। उन्होंने धार्मिक आजादी के भी वादे किये हैं, लेकिन मठों में मार्शल लॉ लगा दिया है। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि चीन ने तिब्बत के बारे में कागज पर तो वादे किये हैं, लेकिन इसके लिए उसने हकीकत में कुछ नहीं किया है।''

सुश्री मेग मन्न : ''आपने मानवाधिकार के जो मुद्दे उठाये हैं, हम लोग उन सभी को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं जानती हूं कि तिब्बत के बारे में उनके पास लंबा रिकॉर्ड है और उन्होंने अनेक अवसरों पर इन मुद्दों को उठाया भी है। हम चीन में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए तीन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं – उच्चस्तरीय लॉबिंग के माध्यम से, ब्रिटेन–चीन और यूरोपीय संघ–चीन के बीच बातचीत के जरिये तथा जमीनी हकीकत में प्रोजेक्ट वर्क के जरिये। इनमें न्यायपालिका, उत्पीड़न, मृत्युदंड और अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इस बहस को आगे बढ़ाते हुए डुंडी वेस्ट से लेबर पार्टी के सांसद श्री जिम मैकगॉवर्न ने सवाल उठाया कि चीन ने मानवाधिकारों को बरकरार रखने के वादे तो किये हैं, लेकिन चीन सरकार की गतिविधियों को देखकर यह समझ पाना कठिन है कि चीन अपने वादे को पूरा करेगा भी या नहीं। क्योंकि कुछ निरंकुश देशों को इसने सहयोग देना जारी रखा है। जिसके परिणामस्वरूप वे देश सुधार की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपीलों को नजरंदाज करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदया सदन को आश्वस्त करेंगी कि उनकी सरकार चीन को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेगी कि वह सुडान जैसे सर्वाधिक निरंकुश देशों को अपने सहयोग पर विचार करे?''

इस सवाल के जवाब में सुश्री मेग मन्न का जवाब था : ''माननीय सदस्य ने महत्त्वपूर्ण सवाल खड़े किये हैं। चीन के साथ हमारी बातचीत हमेशा मानवाधिकार के मुद्दों पर केंद्रित रहती हैं। प्रधानमंत्री जल्दी ही चीन की यात्रा करने वाले हैं और हम बातचीत जारी रखेंगे तथा इन मुद्दों पर दबाव बनाये रखेंगे।''

इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए केन्सिंगटन और चेल्सिया से कंजरवेटिव पार्टी के सांसद सर मैलकोल्म रिफकिन्ड ने सवाल किया कि, ''तिब्बत में मानवाधिकार के मामले में चीन सरकार और कोसोवो में मानवाधिकार के मामले में सर्बिया सरकार के बीच क्या अंतर है?

इसके जवाब में सुश्री मेग मन्न का कहना था : ''हम तिब्बत के मसले को गंभीरता से ले रहे हैं और हमने नियमित बातचीत के दौरान भी इन मसलों को उठाया है। तिब्बत मुद्दे पर ब्रिटेन और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत होगी और इस अवसर पर जमीनी हकीकत के अध्ययन के लिए प्रतिनिधिमंडल तिब्बत की यात्रा भी करेगा।

सुश्री मेग मन्न विदेश एवं राष्ट्रमंडल मामलों की अवर–संसदीय सचिव हैं। ब्रिटिश संसद में हुई इस बहस का पूरा विवरण संसद की आधिकारिक वेबसाइट: *डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पब्लिकेशन्स डॉट पार्लियामेंट डॉट यूके* पर उपलब्ध है।

चीन ने अपने यहां विदेशी पत्रकारों को आजादी देने का वायदा तो किया है, लेकिन उसने अधिकृत तिब्बत में मीडिया पर लगाम और कस दी है। चीनी जेलों और बंदीगृहों तक रेड क्रॉस को पहुंचने देने का वादा तो किया है, लेकिन इस वादे से तिब्बत को अलग रखा है। धार्मिक आजादी के भी वादे किये हैं, लेकिन मठों में मार्शल लॉ लगा दिया है। तब्बत के बारे में कागज पर तो वादे किये हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया है।''

ल्हासा में एक चीन विरोधी प्रदर्शन : सरफरोशी की तमन्ना

तिब्बत में एक साल के भीतर दमनकारी गतिविधियों में तीन गुना वृद्धि

मानवाधिकार संगठन की 2007–रिपोर्ट में तिब्बत की हालत पर चिंता व्यक्त की गई

वर्ष 2007 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तिब्बत में मनमाने तरीके से गिरफ्तारियों और हिरासत के मामलों में 2006 की तुलना में तीन गुना वृद्धि हुई है। संगठन के अनुसार यह दिखाता है कि 2008 में होने वाले बीजिंग ओलम्पिक से पहले वहां मानवाधिकारों की स्थिति और भी बदतर हुई है।

धर्मशाला, 24 जनवरी तिबेतन सेंटर फॉर ह्यूमैन राइट्स एंड डेमोक्रेसी (टीसीएचआरडी) की वर्ष 2007 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तिब्बत में मनमाने तरीके से गिरफ्तारियों और हिरासत के मामलों में 2006 की तुलना में तीन गुना वृद्धि हुई है। संगठन के अनुसार यह दिखाता है कि 2008 में होने वाले बीजिंग ओलम्पिक से पहले वहां मानवाधिकारों की स्थिति और भी बदतर हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष चीन ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाइयां की, जो उसके सख्त रवैये का संकेतक है। यह इसके बावजूद हुआ कि चीन और निर्वासित दलाई लामा के प्रतिनिधियों के बीच छठे दौर की बातचीत प्रस्तावित है।

''तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति : वार्षिक रिपोर्ट–2007'' शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारी चीन के कब्जे वाले तिब्बत में साल भर ऐसे कायदे कानून और फैसले लागू करते रहे, जिससे तिब्बतियों के मानवाधिकारों और उनकी आजादी पर अपना नियंत्रण बढ़ाये जा सके।

तिब्बत में 2007 के दौरान मानवाधिकारों के आकलन से यह बात सामने आई है कि साम्यवादी चीन के अधिकारियों ने तिब्बतियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लगाम कसने के लिए और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करते वक्त मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां करने और तिब्बतियों को हिरासत में लेने के मामलों में तीन गुना वृद्धि से पता चलता है कि वहां मानवाधिकारों की स्थिति बहुत खराब है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत के 119 ज्ञात राजनीतिक बंदियों में से 65 की गिरफ्तारियां 2007 में मनमाने तरीके से की गयीं। इन बंदियों में से कम से कम 43 ऐसे कैदी भी हैं, जो दस वर्ष से अधिक की जेल की सजा काट रहे हैं।

टीसीएचआरडी के निदेशक उरगेन तेनजिन ने आशंका जताई है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत में समुचित आजादी नहीं होने के कारण वहां की आंतरिक स्थिति पर पूरी तरह नजर रख पाना संभव नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, ''तिब्बतियों द्वारा झंडे दिखाकर, अहिंसक प्रदर्शन कर, परमपावन दलाई लामा की तस्वीरें अपने पास रखकर और तिब्बत की आजादी से संबंधित पोस्टर–बैनर दिखाकर किये जाने वाले प्रदर्शनों पर लगाम कसने के लिए चीनी अधिकारी नियमित तौर पर तिब्बतियों को गिरफ्तार करते हैं, उन्हें जेल भेजते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं।''

हालांकि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) को कथित तौर पर अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील क्षेत्र समझा जाता है, लेकिन टीसीएचआरडी के अनुसार राजनीतिक घटनाक्रमों की दृष्टि से टीएआर के बाहर स्थित कारज़े क्षेत्र पिछले कई वर्षों से सर्वाधिक दमन वाला क्षेत्र रहा है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि वर्ष 2007 के दौरान मनमाने तरीके से की गयी 65 गिरफ्तारियों में से करीब आधी कारज़े क्षेत्र से ही की गयी हैं।

रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि तिब्बतियों के बौद्ध मठों और भिक्षुणियों के निवासों पर चीन की दमनात्मक कार्रवाइयां तेज हुई हैं।

कई बार ऐसा होता है कि तिब्बत समर्थक संगठनों द्वारा आयोजित कुछ कार्यक्रमों की रिपोर्टें न उपलब्ध होने के कारण 'तिब्बत देश' में प्रकाशित होने से रह जाती हैं। आयोजकों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रमों की रिपोर्ट और कुछ फोटो की फाइलें (लगभग 500 kb) हमें इस ई–मेल पते पर अवश्य भेजें :

tibbatdesh@yahoo.com

यदि ई–मेल न संभव हो तो इस पते पर भेजें :
'तिब्बत देश', भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र, 10-H लाजपत नगर–3, नई दिल्ली–110024

चीनी अधिकारी लंबे समय से इन मठों और कुटियों को 'विरोधियों का गढ़' मानते रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार ज्ञात राजनीतिक कैदियों में से 70 प्रतिशत (119 में से 80) तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां हैं। चीनी अधिकारियों द्वारा दो नये धार्मिक कानून लागू करने के बाद तिब्बत में वर्ष 2007 के दौरान धार्मिक आजादी हाशिये पर चली गयी। इन दोनों कानूनों के माध्यम से चीन सरकार ने तिब्बती बौद्ध धर्म और इसके आध्यात्मिक गुरूओं पर अपना शिकंजा कस दिया है।

रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि साम्यवादी अधिकारियों ने पूरे वर्ष तिब्बत के विभिन्न क्षेत्रों के मठों और अन्य धार्मिक संस्थानों में राजनीतिक अभियानों के तहत 'देशभक्तिपूर्ण पुनर्शिक्षा' और 'देश से प्रेम करो' जैसे अभियान चलाए, जिनका मुख्य उद्देश्य मठों से जुड़े भिक्षुओं और भिक्षुणियों तथा तिब्बती नागरिकों पर सख्त शिकंजा कसना था।

दुर्गम हिमालय को पार कर तिब्बती शरणार्थियों के विषम परिस्थितियों में तिब्बत से भागने और निरंतर धर्मशाला पहुंचने पर रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2007 में कम से कम 2338 तिब्बती नागरिक निर्वासित तिब्बत सरकार के धर्मशाला स्थित रिसेप्शन सेंटर तक सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहे। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुल तिब्बती शरणार्थियों में से आधे से अधिक 18 वर्ष से भी कम उम्र के हैं, जिन्हें यहां शिक्षा के बेहतर अवसर की आस है। ये शरणार्थी तिब्बत के उन ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं, जहां तीन चौथाई आबादी निवास करती है, लेकिन वहां शिक्षा सुविधाओं का घोर अभाव है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जहां स्कूल हैं भी तो वहां पक्षपातपूर्ण चीनी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

इसके अलावा तिब्बती साइटों और ब्लॉगों को बंद करने, इंटरनेट और अन्य मीडिया पर प्रतिबंध लगाने, तिब्बतियों के किसी धार्मिक या सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने से रोकने के लिए सुरक्षा चाक चौबंद करने, नयी रेल लाइन के शुरू होने से तिब्बत में चीनी नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या और इसकी वजह से तिब्बतियों की परम्परागत आजीविका प्रभावित होने जैसे तमाम पहलुओं पर रिपोर्ट में विस्तृत चर्चा की गयी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ओलम्पिक खेलों के आयोजन में महज कुछ माह शेष रह गये हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन पर दबाव बनाना चाहिए तथा उसके मानवाधिकार सुरक्षित रखने के दावों की पोल खोलनी चाहिए।

एक अगस्त 2007 को पूर्वी तिब्बत में एक बंजारे रोंग्ए आद्राक को गिरफ्तार कर लिया गया था। आद्राक का दोष इतना था कि उसने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 80वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में 'दलाई लामा तिब्बत लौटें', ' पंचेन लामा को रिहा करो' तथा 'आजादी चाहता है तिब्बत' जैसे नारे लगाये। समारोह के मंच पर चढ़कर की गई उसकी इस नारेबाजी में भीड़ भी शामिल हो गई। बाद में चीनी पुलिस ने उसे इस नारेबाजी के लिए गिरफ्तार कर लिया।

तिब्बती बौद्ध धर्म के 'जीवित बुद्ध' माने जाने वाले अवतारी धर्मगुरुओं के चयन के बारे में चीन के धार्मिक मामलों के प्रशासन ने 14 धाराओं वाले कदमों की घोषणा की है जिन्हें एक सितंबर 2007 से लागू कर दिया गया। इन धाराओं में एक धारा यह भी है कि किसी भी अवतारी लामा को तिब्बत से बाहर, खासकर विदेश में पुनर्जन्म लेने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह नए नियमों के मुताबिक हर अवतारी लामा को केवल तभी असली अवतार माना जाएगा जब उसके अवतार होने पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक मुहर लगेगी। पार्टी की यह नई पहल तिब्बत से सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध संस्कृति को दरकिनार करने या उसे मिटाने के प्रयासों की नई कड़ी है। इसके अलावा ये प्रयास बताते हैं कि चीन परम पावन दलाई लामा सहित अन्य तिब्बती धार्मिक नेताओं के प्रभाव को कमजोर करने के लिये कितना बेचैन है।

आज भी चीन 11वें पंचेन लामा गेदुन छ्योकि नीमा के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है जिनका 1995 में अपहरण कर लिया गया था। इसी तरह एक अन्य लोकप्रिय अवतारी लामा तुलकू तेनज़िन देलेक को गलत तरीके से फंसाकर आजीवन कैद की सजा दी गई। अनेक तिब्बती अब भी सींखचों के पीछे हैं जो अपने मूल मानवाधिकारों से वंचित हैं जिन्हें सही सुनवाई का मौका तक नहीं दिया जा रहा।

रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है कि चीन सरकार तिब्बती नस्ल तथा राष्ट्रीय पहचान को ही मिटाने पर तुली हुई है। इसके लिये वह तिब्बत में हान चीनी नागरिकों को धड़ाधड़ बसा रही है। नई रेल लाइन का इस्तेमाल इसी उद्देश्य में किया जा रहा है। इस तरह से तिब्बत का सवाल केवल गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को ही रेखांकित नहीं करता बल्कि यह एक अलग नस्ल, संस्कृति तथा राष्ट्रीय पहचान के रूप में तिब्बतियों के अस्तित्व का सवाल बन चुका है।

दुर्गम हिमालय को पार कर तिब्बतियों के तिब्बत से भागने पर रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गयी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007 में कम से कम 2338 तिब्बती नागरिक निर्वासित तिब्बत सरकार के धर्मशाला स्थित रिसेप्शन सेंटर तक सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहे। इनमें से आधे से अधिक 18 वर्ष से भी कम उम्र के हैं, जिन्हें यहां शिक्षा के बेहतर अवसर की आस है। ये उन ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं, जहां तीन चौथाई आबादी निवास करती है, लेकिन वहां अच्छी शिक्षा सुविधाओं का घोर अभाव है।

फोटो : विजय क्रान्ति

ल्हासा में चीनी कारों की लकदक से हैरान दो तिब्बती भिक्षु : अपने ही घर में पराए

ल्हासा की कारों की बढ़ती संख्या ने चीनी झूठ को बेपरदा किया

तिब्बत में बसाए जा रहे हान नागरिकों ने पिछले साल 70 हजार कारें खरीदीं। टैक्स नीति बदली

चीनी और तिब्बती चेहरों में फर्क करने में अक्षम अनेक पत्रकार यह मान बैठते हैं कि चीन ने तिब्बतियों के लिए बहुत विकास किया है। लेकिन तिब्बत में कारों की संख्या ने चीन के इस दावे की पोल खोल दी है क्योंकि तिब्बत में पंजीकृत हो रही लगभग सभी कारें यहां बस चुके हन चीनियों की हैं।

(चीन सरकार दुनिया को यह दिखाने का ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती कि वह अपने कब्जे वाले तिब्बत में हन समुदाय के लोगों को नहीं बसा रही है।

चीन सरकार का दुष्प्रचार महकमा तिब्बत की प्रायोजित यात्रा पर आए विदेशी पत्रकारों को यह समझाने का भरपूर प्रयास करता है कि तिब्बत का सम्पूर्ण विकास स्थानीय तिब्बतियों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। चीनी और तिब्बती चेहरों में फर्क करने में अक्षम अनेक पत्रकार यह मान बैठते हैं कि आधुनिक भवनों में रहने वाले और शानदार मॉल्स में शॉपिंग करने वाले चीनी नागरिक तिब्बती हैं। लेकिन तिब्बत में कारों की संख्या बढ़ने के बारे में प्रकाशित एक रिपोर्ट से चीन के इस दावे की पोल खुल जाती है क्योंकि तिब्बत में पंजीकृत हो रही लगभग सभी कारें यहां बस चुके हन चीनियों की हैं :– संपादक)

ल्हासा, 8 जनवरी तिब्बत की राजधानी ल्हासा में मोटर वाहनों की संख्या में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखकर तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) में पहली बार वाहन कर लगाया गया है।

कर संबंधी क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कर लगाने से ऊर्जा की बचत के साथ–साथ प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती तो मिलेगी ही, मोटर बाजार पर सरकार का नियंत्रण भी बढ़ेगा। प्रवक्ता ने बताया कि चीन के अन्य हिस्सों में 1994 से ही लागू इस कर की वजह से कार कीमतों का अंतर कम होगा। सरकार ने एक लीटर ईंजन वाली प्राइवेट कार के लिए टैक्स के रूप में 120 युआन प्रतिवर्ष और इससे अधिक बड़े इंजन वाली कार के लिए 360 युआन रखी है। प्रवक्ता के अनुसार यह राशि उन लोगों के लिए मामूली है, जो कार खरीदने का माद्दा रखते हैं।

केंद्रीय चीन सरकार ने पिछले एक दशक से ज्यादा समय से तिब्बत में वाहन कर नहीं लगाने का फैसला किया था क्योंकि यह क्षेत्र अविकसित था। लेकिन पिछले दस वर्षों से अधिक समय से नागरिक वाहन खरीदने वालों की संख्या बढ़ी है और 2006 के अंत तक तिब्बत में 1,43,900 वाहन खरीदे जा चुके थे। इसका सीधा अर्थ है कि प्रत्येक बीस में से एक व्यक्ति के पास मोटर वाहन उपलब्ध हैं।

चार लाख की आबादी वाले ल्हासा में गत वर्ष सितम्बर तक कम से कम 70 हजार वाहन पंजीकृत हो चुके थे और पचास वाहन प्रतिदिन के हिसाब से यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है।

तिब्बत में प्रति व्यक्ति कार ऑनरशिप बीजिंग के बहुत करीब है। बीजिंग की आबादी 1.7 करोड़ है और कारों की संख्या 30.8 लाख। वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण ल्हासा के निवासियों का आम जनजीवन पूरी तरह बदल चुका है।

तिब्बत में आयरन ओर खनन पर रोक

रेलमार्ग से तिब्बती खनिजों की लूट होगी

4 जनवरी चीन सरकार ने कहा है कि वह तिब्बत में असंगठित और गैर–कानूनी खनन गतिविधियों के कारण परेशान है। इस वजह से स्थानीय पर्यावरण को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, तिब्बत में खनिजों के दोहन के सरकारी कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहे हैं। स्वर्ण अयस्क (गोल्ड डस्ट) के दोहन पर प्रतिबंध लगाने के बाद तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) की सरकार ने अब पहली जनवरी से सम्पूर्ण क्षेत्र में लौह–अयस्क (आयरन सैंड) के खनन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।

तिब्बत खनिज सम्पदा के मामले में काफी समृद्ध है, जबकि पर्यावरण की दृष्टि से काफी संवेदनशील। पिछले चार–पांच साल में नए खनिजों के बारे में जारी समाचारों से पता चलता है कि गोरमो से ल्हासा के बीच 1200 किमी लंबी रेल लाइन वाला पूरा तिब्बती इलाका लोहे और तांबे जैसे कई खनिजों से पटा पड़ा है। रेल निर्माण शुरू होने के बाद इन खबरों का जारी करना दिखाता है कि मुश्किल इलाके में रेल निर्माण के पीछे चीन सरकार का एक इरादा तिब्बत के खनिजों का दोहन है।